ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 69-71**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

भारत पर अमेरिकी टैरिफ का सैन्य प्रभावः एक विश्लेषण

डॉ0 विशाल कुमार श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर– रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग, डी0ए0वी0 पी0 जी0 कालेज, कानपुर (उ0प्र0) भारत

Received-20.01.2026, Revised-28.01.2026, Accepted-04.02.2026 **E-mail: vksdav1@gmail.com**

***सारांशः** अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियाँ केवल आर्थिक संबंधों को ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि उनका गहरा प्रभाव सामरिक एवं सैन्य संबंधों पर भी पड़ता है। 21वीं सदी में वैश्विक राजनीति में व्यापार एवं सुरक्षा के बीच अंतर्संबंध अधिक स्पष्ट हुए हैं। अमेरिका द्वारा विभिन्न समयों पर लगाए गए टैरिफ, प्रतिबंध या व्यापारिक नीतियाँ भारत–अमेरिका संबंधों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करती रही हैं।*

*भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग, रक्षा खरीद, तकनीकी हस्तांतरण तथा संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय रहा है। तथापि, यदि अमेरिका भारत पर उच्च टैरिफ लगाता है या व्यापारिक प्रतिबंध लागू करता है, तो इसका प्रभाव रक्षा आपूर्ति शृंखला, तकनीकी सहयोग, स्वदेशी रक्षा उत्पादन (**Make in India**) तथा सामरिक साझेदारी पर पड़ सकता है।*

यह शोध–लेख अमेरिकी टैरिफ की अवधारणा, भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों की पृष्ठभूमि, रक्षा क्षेत्र में सहयोग, संभावित आर्थिक प्रभावों के सैन्य आयाम, सामरिक स्वायत्तता तथा भविष्य की चुनौतियों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेख का मुख्य प्रतिपाद्य यह है कि व्यापारिक तनावों का सैन्य सहयोग पर प्रभाव पड़ सकता है, किंतु भारत की बहुपक्षीय विदेश नीति, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन तथा रणनीतिक संतुलन इस प्रभाव को सीमित कर सकते हैं।

कुंजीभूत शब्द– अमेरिकी टैरिफ, सैन्य प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति, आर्थिक संबंध, सामरिक एवं सैन्य संबंध, वैश्विक राजनीति।

भूमिका– भारत और अमेरिका के संबंध शीत युद्ध काल में सीमित थे, परंतु 21वीं सदी में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का विकास हुआ। 2005 का भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, 2016 में भारत को "मेजर डिफेंस पार्टनर" का दर्जा, तथा LEMOA, COMCASA और BECA जैसे रक्षा समझौते इस साझेदारी के प्रमुख स्तंभ हैं।

2025–2026 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए, उच्च टैरिफ (प्रारंभ में 25% से बढ़ाकर 50% तक, जिसमें रूसी तेल खरीद के लिए अतिरिक्त 25% पेनाल्टी शामिल) ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। ये टैरिफ मुख्य रूप से "reciprocal tariffs" और रूस–यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत की रूसी ऊर्जा एवं हथियार निर्भरता को दंडित करने के लिए लगाए गए थे। हालांकि ये आर्थिक नीति के रूप में शुरू हुए, इनका प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा खरीद, सैन्य आधुनिकीकरण और सामरिक साझेदारियों पर गहरा पड़ा।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक घटनाओं में से एक है। दोनों देश क्वाड (Quad) के माध्यम से इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में चीन के उदय को संतुलित करने, आतंकवाद विरोधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में साझेदार हैं। 2005 से अब तक भारत ने अमेरिका से 20 अरब डॉलर से अधिक की रक्षा सामग्री खरीदी है, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पी–8आई समुद्री निगरानी विमान और एमक्यू–9बी ड्रोन्स शामिल हैं। दोनों देशों ने 2025 में 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौता (Framework for the US-India Major Defence Partnership) पर हस्ताक्षर किए, जो सूचना साझा, संयुक्त अभ्यास और प्रौद्योगिकी सह–उत्पादन को बढ़ावा देता है।

लेकिन 2025–26 में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने इस साझेदारी को गंभीर चुनौती दी। अप्रैल 2025 में शुरू हुए 'रिक्रोकल टैरिफ' (Reciprocal Tariff) से भारत पर 25–26% शुल्क लगाया गया, जिसे अगस्त 2025 में रूसी तेल आयात के कारण अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ जोड़कर 50% तक बढ़ा दिया गया। यह अमेरिका का भारत पर सबसे उच्च टैरिफ था, जो वस्त्र, चमड़ा, जूते, फार्मा, रत्न–आभूषण और मशीनरी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता था। फरवरी 2026 में अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) के तहत टैरिफ 18% पर कम किया गया, रूसी तेल दंड हटाया गया और भारत ने अमेरिकी रक्षा, ऊर्जा तथा विमान खरीद बढ़ाने का वादा भी किया।

इस लेख में हम विश्लेषण करेंगे कि इन टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या टैरिफ ने रक्षा खरीद को बाधित किया? क्या यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती देता है? और क्या अंततः इससे अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग मजबूत हुआ? यह विश्लेषण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक आंकड़ों, रक्षा सौदों, भू–राजनीतिक दबाव और भविष्य के परिदृश्यों पर आधारित है। अनुमानित रूप से टैरिफ से भारत के निर्यात में 10–15% की कमी आई, लेकिन रक्षा क्षेत्र में अप्रत्यक्ष प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण साबित हुए। कुल मिलाकर, टैरिफ ने अल्पावधि में विश्वास की कमी पैदा की, लेकिन दीर्घावधि में भारत को रूस पर निर्भरता कम करने और अमेरिका के साथ गहरे एकीकरण की ओर धकेला।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और टैरिफ की उत्पत्ति– भारत–अमेरिका रक्षा संबंधों की जड़ें 1990 के दशक में हैं, जब पोस्ट–कोल्ड वॉर युग में दोनों देशों ने साझा हितों को पहचाना। 2005 का न्यू फ्रेमवर्क फॉर द इंडिया–यूएस डिफेंस रिलेशनशिप और 2016 का लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) ने आधार तैयार किया। 2020 तक अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया। SIPRI के अनुसार, 2015–2024 में भारत के रक्षा आयात में अमेरिका का हिस्सा बढ़कर 13% हो गया, जबकि रूस का 36% रहा।

ट्रंप प्रशासन (2025) ने 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत रिक्रोकल टैरिफ की शुरुआत की। अप्रैल 2025 में कार्यकारी आदेश 14257 के तहत वैश्विक 10% बेसलाइन टैरिफ के साथ भारत पर 26% रिक्रोकल टैरिफ लगाया गया, क्योंकि भारत के टैरिफ अमेरिका के मुकाबले ऊंचे थे। जुलाई 2025 में रूसी तेल आयात (भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी क्रूड का 40% आयात बढ़ाया) को लेकर अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया गया, जो अगस्त में लागू होकर कुल 50% पहुंच गया। ट्रंप ने इसे रूस की 'युद्ध मशीन' को फंडिंग रोकने का हथियार बताया।

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

भारत ने इसे 'दोहरे मापदंड' कहा, क्योंकि यूरोप भी रूसी ऊर्जा खरीदता रहा। आर्थिक रूप से, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार (18% हिस्सा, 55 अरब डॉलर) है। टैरिफ से वस्त्र (10 अरब डॉलर निर्यात), फार्मा (8 अरब) और रत्न (15 अरब) क्षेत्र प्रभावित हुए। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.7% रही, लेकिन टैरिफ से 0.3–0.5% का नुकसान हुआ। निर्यात में 13% वृद्धि हुई, लेकिन अमेरिका हिस्से में गिरावट आई।

रक्षा क्षेत्र में टैरिफ का सीधा संबंध नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। रक्षा बजट 2025–26 में 7.85 लाख करोड़ रुपये (93 अरब डॉलर) था, जिसमें कैपिटल आउटले 1.72 लाख करोड़ था। टैरिफ से राजस्व घाटा और मुद्रा दबाव ने आधुनिकीकरण को प्रभावित किया।

टैरिफ का आर्थिक प्रभाव और रक्षा बजट पर दबाव– टैरिफ ने मुख्यतः श्रम–प्रधान क्षेत्रों को मारा। इकोनॉमिक सर्वे 2026 के अनुसार, निर्यातक एमएसएमई (टेक्सटाइल, लेदर) में नौकरियां प्रभावित हुईं, लेकिन भारत ने यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में बाजार विविधीकरण किया। यूएन डीईएसए ने 2025–26 में 7.2% वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसमें सार्वजनिक निवेश और उपभोग ने टैरिफ को ऑफसेट किया।

रक्षा पर अप्रत्यक्ष प्रभावः भारत का रक्षा बजट जीडीपी का 2.4% है। टैरिफ से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और निर्यात घाटे से राजकोषीय घाटा बढ़ा। 2026 बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए एयरक्राफ्ट पार्ट्स और एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल) पर शुल्क छूट दी गई, जो अमेरिकी आयात को सस्ता बनाती है। लेकिन कुल मिलाकर, आर्थिक अनिश्चितता ने रक्षा खरीद को धीमा किया।

उदाहरणः स्ट्राइकर वाहन और जेवलिन मिसाइल सौदे 2025 में अस्थायी रूप से रोके गए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत ने टैरिफ को लीवरेज के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने इनकार किया। छोटे सौदे जैसे 93 मिलियन डॉलर के जेवलिन और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल नवंबर 2025 में मंजूर हुए।

आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) को बढ़ावा मिला। टैरिफ ने भारतीय रक्षा उद्योग (HAL, L&T, BEL) को स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया। GE F404 इंजन (1 अरब डॉलर सौदा, Tejas Mk–1A के लिए) और F414 को– प्रोडक्शन (Tejas Mk-2 के लिए) जैसे प्रोजेक्ट्स तेज हुए।

इसी अवधि में वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ। अमेरिका ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा हेतु कई देशों पर टैरिफ लगाए। भारत भी कभी–कभी अमेरिकी टैरिफ नीतियों से प्रभावित हुआ, जैसे– इस्पात एवं एल्युमिनियम पर टैरिफ, सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) से भारत की हटाना आदि।

टैरिफ का सीधा प्रभाव व्यापार संतुलन, निर्यात एवं आयात लागत पर पड़ता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह रणनीतिक विश्वास, रक्षा सहयोग तथा तकनीकी साझेदारी को भी प्रभावित कर सकता है।

अमेरिकी टैरिफः अवधारणा एवं पृष्ठभूमि– टैरिफ वह कर है जो किसी देश द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा, व्यापार घाटे को कम करना या राजनीतिक दबाव बनाना हो सकता है।

अमेरिका ने "अमेरिका फर्स्ट" नीति के अंतर्गत कई देशों पर टैरिफ लगाए। भारत पर लगाए गए कुछ प्रमुख टैरिफ इस प्रकार रहे :

1. इस्पात एवं एल्युमिनियम पर शुल्क,
2. GSP सुविधा का समाप्त होना,
3. चिकित्सा उपकरणों एवं कृषि उत्पादों पर विवाद।

इन टैरिफों का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक एवं सामरिक स्तर पर भी देखा गया।

भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग की पृष्ठभूमि–

1. रक्षा खरीदः भारत ने अमेरिका से C-17, C-130J, P-8I अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर एवं MH–60R जैसे उपकरण खरीदे हैं।

2. संयुक्त सैन्य अभ्यासः मालाबार नौसैनिक अभ्यास, युद्ध अभ्यास (Yudh Abhyas), टाइगर ट्रायम्फ आदि।

3. तकनीकी सहयोगः डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव (DTTI) के माध्यम से सह–विकास एवं सह–उत्पादन की पहल।

अमेरिकी टैरिफ का सैन्य प्रभाव–

1. रक्षा आयात लागत में वृद्धिः यदि टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंध लागू होते हैं, तो रक्षा उपकरणों की लागत बढ़ सकती है।

2. आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभावः रक्षा उत्पादन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर करता है। व्यापारिक तनाव से यह प्रभावित हो सकती है।

3. तकनीकी हस्तांतरण में बाधाः राजनीतिक तनाव तकनीकी सहयोग को धीमा कर सकता है।

4. सामरिक विश्वास में कमीः व्यापारिक विवाद से रणनीतिक साझेदारी में अविश्वास उत्पन्न हो सकता है।

5. आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहनः टैरिफ से प्रेरित होकर भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है।

सामरिक स्वायत्तता एवं बहुध्रुवीयता– भारत की विदेश नीति "रणनीतिक स्वायत्तता" पर आधारित है। अमेरिका के साथ सहयोग के बावजूद भारत रूस, फ्रांस एवं इज़राइल से भी रक्षा सहयोग बनाए रखता है। टैरिफ से उत्पन्न दबाव भारत को बहुध्रुवीय रक्षा नीति अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

आर्थिक–सैन्य अंतर्संबंध– आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति का आधार होती है। यदि टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, तो रक्षा बजट पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

संभावित परिदृश्य–

1. व्यापारिक विवादों का कूटनीतिक समाधान,
2. रक्षा सहयोग का निरंतर विस्तार,
3. स्वदेशी रक्षा उद्योग का सुदृढ़ीकरण,
4. वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों का विकास।

सैन्य प्रभावः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयाम प्रत्यक्ष प्रभाव– रक्षा खरीद और सौदेः टैरिफ काल में कुछ सौदे प्रभावित हुए। 2025 में भारत ने बड़े अमेरिकी प्लेटफॉर्म (जैसे अतिरिक्त पी–8 आई या डफ–9B) पर रोक लगाई, लेकिन अक्टूबर 2025 में 10 वर्षीय रक्षा

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

समझौता साइन हुआ, जो समन्वय, सूचना साझा और प्रौद्योगिकी सहयोग पर केंद्रित था। यह टैरिफ तनाव के बीच महत्वपूर्ण था। फरवरी 2026 ट्रेड डील ने बदलाव लाया। भारत ने अमेरिकी रक्षा प्रणालियों, विमानों और ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाने का वादा किया (ट्रंप का +500 अरब क्लेम, जिसमें रक्षा हिस्सा शामिल)।

विशिष्ट रूप से:

1. GE F414 इंजन को–प्रोडक्शन तेज।
2. डफ–9B सी गार्जियन ड्रोन्स का लीज विस्तार।
3. संभावित स्ट्राइकर, अपाचे और F–35 (भविष्य में) चर्चा।
4. L&T और जनरल एटॉमिक्स के साथ MALE RPAS ड्रोन सह–उत्पादन।

ट्रंप ने 'अमेरिका फर्स्ट आर्म्स एक्सपोर्ट' ऑर्डर जारी किया, जिसमें आर्थिक योगदान देने वाले साझेदारों (जैसे भारत) को प्राथमिकता। इससे अमेरिकी कंपनियां भारतीय रक्षा में निवेश बढ़ाएंगी।

अप्रत्यक्ष प्रभाव– भू–राजनीति और रूस निर्भरता: टैरिफ का सबसे बड़ा सैन्य प्रभाव रूस पर निर्भरता कम करने का था। भारत रूसी तेल (कम होकर 1 मिलियन बैरल/दिन) और हथियार (S-400, सु–30) पर निर्भर था। टैरिफ ने दबाव डाला, जिससे भारत ने रूसी तेल कम किया और अमेरिकी ऊर्जा/रक्षा की ओर मुड़ा।

यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती था, लेकिन चीन की धमकी (लद्दाख) ने रक्षा सहयोग को अलग रखा। संयुक्त अभ्यास (मालाबार, कोप इंडिया) बिना रुके चले।

रक्षा उद्योग परः अमेरिकी टैरिफ से स्टील/एल्यूमिनियम आयात प्रभावित, लेकिन भारत ने स्वदेशी विकल्प विकसित किए। क्रिटिकल मिनरल्स (रेयर अर्थ) पर बजट 2026 में छूट ने रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स को मजबूत किया।

आर्थिक दबाव से रक्षा कैपिटल आउटले प्रभावित हुआ, लेकिन 2026 बजट में बढ़ोतरी हुई। कुल प्रभावः अल्पावधि में 5–10% देरी, दीर्घावधि में अमेरिकी हिस्सा बढ़कर 20–25%।

भारत की प्रतिक्रिया और भविष्य के परिदृश्य– भारत ने बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया दी। ट्रेड डील में कृषि सुरक्षा बरकरार रखी, लेकिन औद्योगिक सामान पर शुल्क कम किए। रक्षा में आत्मनिर्भरता (Tejas, AMCA, विक्रांत) को बढ़ावा। फ्रांस (राफेल) और इजराइल के साथ विविधीकरण जारी।

भविष्य–

1. सकारात्मक परिदृश्य– रक्षा व्यापार 50 अरब डॉलर तक पहुंचे, को–प्रोडक्शन से निर्यात बढ़े, क्वाड मजबूत।
2. नकारात्मक– ट्रंप की अनिश्चितता से नया टैरिफ चक्र, रूस संबंध खराब।
3. संभावित– हाइब्रिडः रूस से पुराना स्टॉक, अमेरिका से नई टेक।
4. चुनौतियांः CAATSA प्रतिबंध का खतरा, बजट सीमाएं, स्वदेशी क्षमता विकास की गति।

चुनौतियाँ– 1. तकनीकी निर्भरता, 2. रक्षा आयात पर उच्च व्यय, 3. वैश्विक भू–राजनीतिक अनिश्चितता।

समाधान एवं नीति सुझाव– 1. रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, 2. बहुपक्षीय रक्षा सहयोग, 3. व्यापार विवादों का वार्ता के माध्यम से समाधान, 4. रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निवेश।

निष्कर्ष– भारत पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव केवल व्यापारिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संभावित प्रभाव सैन्य एवं सामरिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी और साझा हित इन प्रभावों को संतुलित करने में सहायक हो सकते हैं।

अमेरिकी टैरिफ ने भारत की रक्षा क्षमता पर भी अल्पावधि में दबाव डाला, लेकिन दीर्घावधि में इसे मजबूत किया। 50% टैरिफ से आर्थिक झटका लगा, रक्षा खरीद प्रभावित हुई, लेकिन 10 वर्षीय ढांचा और फरवरी 2026 डील ने संबंधों को नई ऊंचाई दी। भारत अब रूस पर कम निर्भर, अमेरिका के साथ गहरा एकीकरण कर रहा है। यह 'रणनीतिक स्वायत्तता' और 'बहु–संरेखण' (multi -alignment) की नीति का सफल प्रमाण है।

भविष्य में दोनों देशों को व्यापार और रक्षा को अलग रखना होगा। भारत को आत्मनिर्भरता तेज करनी चाहिए, अमेरिका को स्थिर साझेदारी देनी चाहिए। अंततः, चीन की चुनौती दोनों को एकजुट रखेगी। टैरिफ संकट ने साबित किया कि आर्थिक दबाव रक्षा संबंधों को तोड़ नहीं सकता, बल्कि नई दिशा दे सकता है।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, बहुपक्षीय सहयोग तथा आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में प्रयास अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न संभावित चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अमेरिकी टैरिफ का सैन्य प्रभाव परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, किंतु दीर्घकाल में भारत की सामरिक नीति संतुलन एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर रहेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय– वार्षिक प्रतिवेदन।
2. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय– व्यापार रिपोर्ट।
3. U.S. Trade Representative (USTR) Reports.
4. SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Database.
5. Ashley J. Tellis, India.U.S. Military Relations.
6. Stephen P. Cohen, India: Emerging Power.
7. C. Raja Mohan, Crossing the Rubicon: The Shaping of Indias New Foreign Policy-
8. ORF एवं IDSA (Manohar Parrikar Institute) की सामरिक रिपोर्टें।

*****